

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

SHRI K LAKKAPPA: I introduce the Bill.

15.31 hrs.

MONOPOLIES AND RESTRICTIVE
TRADE PRACTICES (AMENDMENT)
BILL*

Amendment of Sections 21, 22 etc.

SHRI SOUGATA ROY (Barrack-pore): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969

MR DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969."

The motion was adopted.

SHRI SOUGATA ROY: I introduce the Bill.

15.32 hrs.

JUTE MILL COMPANIES (ACQUI-
SITION AND TRANSFER OF
UNDERTAKINGS) BILL*

SHRI SOUGATA ROY (Barrack-pore): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the acquisition and transfer of undertakings of the Jute mill companies.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the acquisition and transfer of undertakings of the jute mill companies."

The motion was adopted.

SHRI SAUGATA ROY: I introduce the Bill.

15.33 hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT)
BILL—contd.

(Omission of article 310. etc.) by Shri Bhagat Ram

MR DEPUTY-SPEAKER. We continue with the further consideration of the Constitution (Amendment) Bill moved by Shri Bhagat Ram. He was on his legs.

श्री भगत राम (फिल्लौर) - मिस्टर डिप्टी स्पीकर मर, पिछले 9 सार्च को मैंने बोलने हुए कहा था कि हमारे कांस्टीट्यूशन की जो धाराएं 310 और 311 हैं, उनके द्वारा हमारे सेक्टर के 30 लाख और स्टेट्स के 40 लाख एम्प्लॉय के डेमोक्रेटिक राइट्स को छीना गया है। यही नहीं, बल्कि मैं तो यह भी कहूंगा कि ये जो हमारे कांस्टीट्यूशन की धाराएं हैं, वे बिल्कुल एंटी डेमोक्रेटिक हैं और ये प्राकृतिक न्याय की भी विरोधी हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, आपकी मायूम ही है कि चाहे चीर डी, चाहे डाकू हो, चाहे स्मगलर हो, चाहे कोई कातिल हो, सब को अपने डिफेंस का राइट है। परन्तु इन धाराओं के द्वारा, जिन एम्प्लॉय पर ये धाराएं लागू की जाती हैं, उनको प्राकृतिक न्याय भी नहीं मिलता है जब कि कोई चोरी करे, डाका डाले, स्मगलिंग करे, कत्ल करे, उसको प्राकृतिक न्याय मिलता है। उनको अपना पक्ष पेश करने का हक है। लेकिन जिन लोगों पर ये धाराएं लागू होती हैं, उनको अपना डिफेंस करने का कोई हक लागू नहीं होता है। ये धाराएं जहां बेहूदा हैं, एंटी डेमोक्रेटिक हैं वहां ये धाराएं प्राकृतिक न्याय की भी विरोधी हैं। इन धाराओं को हमारे संविधान से खारिज करने के लिए केन्द्रीय और प्रांतीय सरकारों में जो एम्प्लॉय की सुनियमन हैं, केन्द्रीय हैं, वे दसियों सालों से संघर्ष करती चली आ रही हैं और यह मांग करती चली आ रही हैं कि इनको हमारे संविधान से खाल किया जाए।

*Published in Gazette of India Extraordinary Part II, Section 2, dated 23-3-1979.

†Introduced with the recommendation of the President.

पिछले साल आब इंडिया स्टेट एम्प्लाइज फंडेशन की पटना में एक कनवेंशन हुई थी जिस में उन्होंने इन अनुच्छेदों को लोप करने के प्रस्ताव पास किए, फिर आब इंडिया रेलवेमैज फंडेशन ने इसी आनरेबल हाउस में एक पेटिशन पेश की और उस में भी यही मांग की कि एम्प्लायज को राजनीतिक और डेमोक्रेटिक राइट्स मिलने चाहियें। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाइज कनफेडरेशन जो केन्द्रीय कर्मचारियों की नुमाइंदगी करती है उन्होंने भी कई बार यह मांग को है। सभी यूनियनों या एसोसिएशनों जो सरकार की दलाल नहीं हैं और सही मानों में सरकारी कर्मचारियों की नुमाइंदगी करती हैं, जो सरकार की चमचागीरी नहीं करती हैं, जो अपने साथी मूलाजिम हैं उन में विश्वास रखती है, सभी ने मांग की है कि ये बेहूदा अनुच्छेद हैं इनको जितनी जल्दी हो सके संविधान से खारिज किया जाए।

जनता पार्टी ने भी अपने चुनाव घोषणापत्र में सरकारी कर्मचारियों के साथ यह वादा किया था कि हम उनको डेमोक्रेटिक राइट्स देंगे। इसको मैं कोट करना चाहता हूँ। पेज 16 पर 19वें पैरे में इन्होंने लिखा है।

ऐसा प्रबन्ध करेंगे कि सरकारी कर्मचारियों का उत्पीड़न न किया जा सके, उन पर कोई राजनीतिक दबाव न पड़ने पाए और उनको गैर कानूनी आदेश मानने के लिए तथा गैर कानूनी काम करने के लिए बाध्य न किया जा सके। न्यायालयों का आश्रय लेने का उनका अधिकार उन्हें वापिस मिलेगा।

इस तरह से सरकारी कर्मचारियों को डेमोक्रेटिक राइट्स देने का जनता पार्टी ने भी वादा किया हुआ है। मुझे खुशी है कि जनता पार्टी ने पावर में आ कर लोगों की भावनाओं को समझते हुए एमरजेंसी के जमाने में बनाए गए काले कानूनों को खत्म किया। इस में सभी डेमोक्रेटिक पार्टियों ने उसको स्पॉर्ट किया है। इस बातसे मैं अपील करता हूँ कि उसने अपने चुनाव घोषणापत्र में जो वादा किया है इसको भी वह पूरा करे।

1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद महारानी क्विंजरिया ने एक एलाननामा जारी किया था और उसके बाद 1935 का गवर्नमेंट आफ इंडिया एक्ट बना था, उनमें ये जो धारायें थीं इन धाराओं को हमारे संविधान को बनाने वालों ने ज्यों का त्यों ले लिया था। जब हमारा देश विदेशी शासकों के अधीन था सब उनको इस तरह के कानूनों को जरूरत थी, इस तरह की धाराओं को जरूरत थी ताकि वे हिन्दुस्तान पर आसानी से राज्य करते रह सकें और ऐसे आटोक्रैटिक कानूनों को भारतीयों पर लागू कर सकें और उनका इस्तेमाल कर के लोगों को दबाए रख सकें। अपने राज्य को चालू रखने के लिए उनके लिए यह जरूरी था। लेकिन जब देश आजाद हुआ तब भी इस तरह के कानूनों को जो विरामन से लिया गया है उनको संविधान में ज्यों का त्यों रख दिया गया। विदेशी शासकों की ब्यूरोक्रेसी यहां के एम्प्लायज की देश भक्ति की थोड़ी बहुत भावना को भी सहन नहीं कर सकती थी और उन्होंने इस तरह

के कानून बना रखे थे। हमें आजाद होने के बाद यही ब्यूरोक्रेसी विरासत में मिली। इसके आचार विचार में स्वभाव में कोई फर्क नहीं आया। इसको भी कर्मचारियों से उसी प्रकार का भय बना रहता था जिस प्रकार का भय विदेशी शासन के समय ये महसूस करती थी। स्वतंत्रता के बाद जब हमारे देश को बागडोर यहां के शोषक वर्ग के हाथ में आई और उनका भी इसी में इन्टरैस्ट था कि ऐसे प्रावधान हमारे संविधान में हों जिनके द्वारा वे शोषक वर्ग तर सदियों तक अपना राज्य जारी रख सकें। इसलिये ब्रिटिश समय से यहां चली आ रही जो ब्यूरोक्रेसी थी और जो शोषक शासक वर्ग था उन्होंने इस सब के लिये कोलेबोरेशन किया और ऐसी कई धाराओं बनाये रखीं जो क्रूर हैं, जिनको हमारी पार्टी जनता पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टियां कहती हैं कि क्रूर हैं, फिर भी उनको विधान में ज्यों का त्यों बनाये रखा। विदेशी समय की कई धारायें ज्यों की त्यों लगी हुई हैं और बिना सोचे समझे कर्मचारियों पर उनका इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि उन तो राष्ट्रपति और न गवर्नर सीर तर पर कर्मचारी को व्यक्तिगत रूप से जानता है, उनको पता भी नहीं होता कि कौन कहां पर काम करता है, लेकिन जब उनके डिमिसल का आदेश होता है तो उन पर यह धारा लागू होती है और उस डिमिसल आर्डर पर या तो गवर्नर या राष्ट्रपति के दस्तखत होते हैं। होता क्या है कि जो एम्प्लाइज ईमानदारी से काम करना चाहते हैं और अपने बौस के करणन को सहन नहीं करते हैं, उस पर एतराज करते हैं तो कुछ भ्रष्ट अधिकारी लोग ऐसे ईमानदार कर्मचारियों से जलते हैं और उन पर अत्याचार करते हैं, जो करेक्टर रोल की प्रथा हमारे देश में ब्रिटिश समय से चली आ रही है उसको खराब कर देते हैं और धीरे धीरे यह धारा लगा देते हैं ताकि उनका करणन जारी रहे। हमारे राष्ट्रपति और गवर्नर बिना सोच विचार किये उस पर दस्तखत कर देते हैं।

दूसरे यह कि अपना पोलिटिकल मोटिव सर्व करते के लिये जो शोषक शासक वर्ग होता है वह अपने शासन को आगे बढ़ाने के लिये और ट्रेड यूनियन तथा डेमोक्रेसी को कल्ल करने के लिये इसका इस्तेमाल करता है। क्योंकि जो ट्रेड यूनियन के नुमाइन्दे होते हैं, जो सरकारी कर्मचारियों की नुमाइन्दगी करते हैं वे लोग अपनी मांगों के लिये जत्याबन्दी करते हैं, संघर्ष करते हैं, तो सरकार उसको सहन नहीं करती है। तो कर्मचारियों को अपने लीडर से अलग करने के लिये, उनकें मूवमेंट को लीडरलैस करने के लिये इस धारा का इस्तेमाल करते हैं। और यही कारण है कि पिछले समय बंगाल में 13 स्टेट एम्प्लाइज जो कोआर्डिनेशन कमेटी के लीडर थे और जो बड़े पौपुलर थे, जिनको हर तरह से कर्मचारियों की सपोर्ट थी, उनको श्री सिद्धार्थ रे को मिनिस्ट्री के समय बिना कोई कारण बताये इसी धारा को लगा कर के नौकरी से निकाला गया था। और उसी समय बंगाल में ही कोसीपुर और ईशापुर आर्डिनेंस फ्रैक्चरियां जो बंगाल में हैं वहां के 32 कर्मचारियों को भी यही धारा लगा कर निकाला गया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर तथा और भी कई राज्यों में जो कर्मचारियों की नुमाइन्दगी करते थे उनको इस धारा का शिकार होना पड़ा। यह बेहूदा धारा है जिसको इमरजेंसी के दौरान बड़ी

[श्री भगत राम]

बेरहमी के साथ इन्तेमान किया गया। आपका मालूम है कि इमजेंसी लगा कर श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार ने हमारे देश के लोगों के मारे नागरिक अधिकारों को छीन लिया था और इमजेंसी प्रोबोजन को ले कर देश की बकिंग क्लाम पर और ऐम्प्लॉईज पर अन्याचार किये गये। गह बात हिन्दुस्तान के मारे लोग ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के लोग जानते हैं।

आपको मालूम है कि इमजेंसी के दौरान ऐम्प्लॉईज के कंडरट रुज्ज को चेंज किया गया, ताकि उनपर नसबंदी कराने के लिये दबाव डाला जा सके। उनके काम के बोझ को बढ़ा दिया गया। सी० डी० एम० खत्म होने वाला था, मगर उनका और धागे बढ़ा दिया गया। इस के अलावा सरकारी कर्मचारियों का हाफ परसेंट डी० ए० वाट दिया गया। इस सरकार के लिए यह बड़े धर्म की बात है कि उस ने इसी तरह इमजेंसी में काटे गये हाफ परसेंट डी० ए० का भी बहाल नहीं किया है। सरकारी कर्मचारियों पर और भी बड़े अन्याचार किये गये।

सरकारी कर्मचारियों का डर था कि अगर हम अपनी मांगा के लिए धरना देंगे, मज्जुदाह्म करगे या शान्तिपूर्ण ढंग से एजीटेशन करेंगे, तो प्रांटिकल 310 और 311 (2) (सी) का इन्तेमान कर न पड़े हम नौबरी से निकाल न दिया जाये। इमजेंसी के दौरान सरकारी कर्मचारियों की ट्रेड यूनियन सबमेट मारी की मार्ग ठप कर दी गई। लेकिन फिर भी सरकार का नसन्नी नहीं हुई और इन प्रांटिकल का इन्तेमान कर के सैकड़ों सरकारी कर्मचारियों का नौबरी से निकाल दिया गया। जा शरीफ और ईमानदार कर्मचारी थे, जो ईमानदारी से अपना काम करते थे, मगर अपने कुछ छुट्टे वासित्त की दुर्भावनाया की बंद नहीं करने थे, उन्हें भी निकाला गया और जो कर्मचारियों की नुमाइशगी करने थे या ट्रेड यूनियन के लीडर थे, उन्हें भी निकाला गया। वगाल में सरकारी कर्मचारियों के 15 लीडरों का इस प्रांटिकल का इन्तेमान कर के निकाला गया। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के सैकड़ों सरकारी कर्मचारियों का इस प्रांटिकल के तहत निकाला गया। कम्पनरी गिटायगमेंट की गई। इमजेंसी में यह सब कुछ हुआ, लेकिन सरकारी कर्मचारियों का प्रांटिकल के डर की वजह से कार्टे प्राटेस्ट न कर सके।

आपको पता है कि इमजेंसी के दौरान यहा पर कोई प्राटेस्ट नहीं हो सकता था, सब अधिकार छीन लिये गये थे। इस लिए सीटू-सेटर आफ ट्रेड यूनियन—ने इंटरनैशनल नेबर धार्गनाइवेशन यानी आई० एल० प्रो० से शिकायत की कि हिन्दुस्तान में ट्रेड यूनियन और डेमोक्रेटिक राइट्स का कल्ल किया गया है और सरकारी कर्मचारियों पर तरह तरह के अन्याचार किये गये हैं। सी० आई० डी० ए० का लैटर बहा तक नहीं पहुंच सका, क्योंकि मिनिस्ट्री आफ कम्पनिकेशन्स में इमजेंसी महारानी इन्चिदर भी के खान हुबखम्ब ने उन लैटर को रोक लिया और बहा तक नहीं पहुंचने दिया। तब सीटू ने किसी दूसरे देश से आई० एल० प्रो० को

लटर भिजवाया, और वह लटर उनको मिला। उन्होंने उस पर बिचार किया और उनकी 172वीं रिपोर्ट में कमेटी ऑन फीडब आफ एसीसियेशन आफ दि आई० एल० प्रो० ने इस बारे में जो प्राबजर्वेशन्स दी, मैं उन्हें कोट करना चाहता हूँ।—

The CITU had referred to the situation of employees of the state government stating that in West Bengal, the Government had arrested and dismissed 15 union leaders, including the Secretary of the State Coordination Committee of the West Bengal Government Employees' Association.

धागे में और धांजा काट करना चाहता हूँ।

“... and Unions under article 311(2)(c) of the Indian constitution, this committee, which had already been the victim of earlier measures was, nevertheless, according to the complainant, not a political organisation but was pursuing legitimate trade union activities. The CITU had also mentioned the cases of senior union leaders who had been dismissed or arrested in Tripura, Jammu and Kashmir. The complainants had also referred to dismissals of many workers in the States of Uttar Pradesh, Orissa, Har-yana, Rajasthan and Madhya Pradesh.

धागे और प्राबजर्वेशन है :

“In a letter of 9 September 1976 the CITU had enclosed a list of 25 union leaders in West Bengal, in the service of the central or state governments, who had been detained without trial under the Maintenance of Internal Security Act and served with dismissal notice. According to the CITU, 16 of them had been released on 8 November 1975 but they had not been reinstated in their employment. The remaining nine were still in detention under lamentable conditions and were being treated as criminals, their health

had deteriorated in the course of their prolonged detention.”

यह सब शिकायत थी। उस पर जो एमजेंसी की महारानी इन्दिरा थी, जब उन से पूछा गया कि यह सब हिन्दुस्तान में क्या हो रहा है, इस के बारे में आप का क्या विचार है तो उन को सरकार से उन को यह जवाब मिला :

“To these allegations the Government had responded that any dismissals which took place under article 311(2)(c) of the Indian constitution again had nothing to do with the trade union activities of the persons concerned. According to the Government any such action was taken on the merits of each individual case and was not limit to any particular trade union or political denomination.”

यह आई एल ओ की आबजर्वेशन है कि किस किस ढंग से 310 और 311 धाराओं का इस्तेमाल हमारे देश की जो एम्प्लाइज मूवमेंट थी, उस को रूढ़ करने के लिए, उस को लीडरलेस करने के लिए और अपने पोलिटिकल मोटिव को सर्व करने के लिए भिन्न भिन्न सरकारों ने किया। लेकिन यह खुशी की बात है कि यह जो मौजूदा सरकार है इस सरकार ने एमजेंसी के दौरान इस धारा के अन्तर्गत जो नौकरियों से निकाले हुए एम्प्लाइज थे, लीडर थे उन को बहाल कर लिया है और बैस्ट बंगाल तथा त्रिपुरा की गवर्नमेंट ने भी अपने एम्प्लाइज को बहाल कर लिया है। उन के बाद जो उन का काम है खास तौर से वो फ्लड्स आई हैं उन फ्लड्स में उन लीडर्स ने अपनी यूनियन को इस ढंग से होल हाटेंडली जो फ्लड अफेक्टेड थे उन की सेवा के लिए लगाया है कि सब लोग देख कर हैरान रह गए कि कैसे, पिछली गवर्नमेंट इन को किमिनल समझती रही है और वे लोग कैसे फ्लड अफेक्टेड लोगों की सेवा कर रहे हैं। इसलिये मैं यह बताना चाहता हूँ कि यह जो आर्टिकल है यह अगर कोई देशाही है तो उस पर आज तक इस्तेमाल नहीं हुई, बल्कि जो देश भक्त हैं जो असली माने में ट्रेड यूनियन्स के द्वारा देश की सेवा करना चाहते हैं उन पर ये धाराएँ इस्तेमाल की गई हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारी जनता पार्टी जो डेमोक्रेटिक वेल्युज को रेस्टोर करने का वादा कर के ताकत में आई है उसने एमजेंसी के जो विक्टिम हैं उन को वो बहाल कर दिया है लेकिन पिछले समय में पिछली सरकार ने इसी धारा के तहत जिन एम्प्लाइज को डिसमिस किया था वे ज्यों के त्यों हैं—अभी तक उनको बहाल नहीं किया गया है। रेलवे और दूसरे इस्टेब्लिशमेंट्स के एम्प्लाइज अभी भी नौकरी से बाहर हैं। जरूरत इस बात

की थी कि उनको भी री-इंस्टेट किया जाता जैसे पश्चिमी बंगाल की सरकार ने किया लेकिन सरकार उनको री-इंस्टेट करने में पूरी तरह से फेल हुई है। इसीलिए मैंने कहा है कि यह जरूरी नहीं है कि सिर्फ पिछली सरकार ही इसका दुरुपयोग करती रही है, यह सरकार उसका दुरुपयोग नहीं करेगी। इस बात पर इसलिये यकीन नहीं आ रहा है क्योंकि पिछली सरकार और कई इमजेंसी के विक्टिमस को अभी तक न्याय नहीं मिला है। जब तक उन लोगों को न्याय नहीं मिलता तब तक इस बात पर यकीन नहीं किया जा सकता कि यह सरकार इसका दुरुपयोग नहीं करेगी जो इण्डस्ट्रियल रिलेशन्स बिल आया था उसका समूची मजदूर जमात ने डट कर विरोध किया है और जनता पार्टी के अनेक सदस्यों ने भी उसका विरोध किया है अभी किसी सरकारी इदारे में कोई छोटा मोटा संघर्ष होता है या किन्हीं मांगों को लेकर मजदूरों की कोई हड़ताल होती है तो हमारे देश के प्रधान मंत्री जो यह शर्त रखते हैं कि जब तक वे अपना संघर्ष नहीं छोड़ते तब तक कोई बात नहीं की जा सकती। जब तक यह सरकार इस तरह की बातें करती है तब तक इस बात पर यकीन नहीं किया जा सकता कि आने वाले समय में इसका कोई दुरुपयोग नहीं किया जायेगा। मुझे फख है कि सरकारी कर्मचारियों की भावनाओं की तरजुमानी करते हुए इस माननीय सदन के सामने मैंने इस धारा को खारिज करने का बिल पेश किया है।

आई एल ओ के 64वें सेशन में, जोकि 1978 में हुआ था, इस सवाल पर विचार किया गया था। मैं कोट करना चाहता हूँ :

Employees' organisations enjoy complete freedom from public authorities. Employees' organisations shall enjoy adequate protection against any acts of interference by a public authority in their establishment, functioning or administration.

आर्टिकल 310, 311(2)(सी), अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर फ्रीडम आफ एसोसियेशन के कांसेप्ट के विरुद्ध है। सरकारी कर्मचारियों को इस बात का कानूनी अधिकार होना चाहिए। अगर सरकार गुलाम और मालिक के रिलेशन्स रखकर सरकारी कामों में एफिक्टिविटी एण्ड एफिसिएन्सी लाने की बात सोचती है तो वह उसकी गलती है। यह तबेज भी ठीक चल सकता है, जब सरकारी सर्विसेज में डेमोक्रेटिक वेल्युज की कदर की जायेगी और उन को बहाल किया जायेगा।

इस सरकार में बहुत से ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने एमजेंसी के दौरान बड़ी जेलें काटी हैं, महारानी इन्दिरा का बड़ा तशब्द सहन किया है। इन में बहुत से लोग ऐसे हैं जो पिछले समय

[श्री भगत राम]

में हम अनुच्छेद को खारिज करने के लिये लगाना चाहते हैं, लेकिन आज मुझे पैरानी है, हमारे विजय सर्वथी जार्ज फर्ग्युसन मध्य उच्चकोर्ट में अपील कर रहे हैं और उनके जैसे ट्रेड यूनियनियन्ट्स जिन्होंने हमेशा इस के खिलाफ आवाज बुलन्द की है, चुप क्यों बैठे हैं, इन दो पार्टीकलर को खारिज करने के लिये जोर क्यों नहीं लगा रहे हैं ? मैं आज जनता सरकार से, जनता पार्टी के मेम्बरान से और जिनकी दूसरी पार्टीया गठों पर है उन के मेम्बर साहबान से अपील करूँगा कि हम विजय को, जिसे मैंने पेश किया है, जो 70 लाख से ज्यादा के लिये और राशियों के सर्कारों के कामकाजों को भावनाओं को नरामाना करना है, हम पर गम्भीरता से विचार किया जाये और हमें पाम दिया जाये ताकि हिन्दुस्तान के मंत्रिकालन में जो बड़े दो पार्टीकलर हैं उन को निवाला जा सके ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

"That the Bill further to amend the Constitution of India be taken into consideration."

SHRI VIJAYKUMAR N. PATIL (Dhulia): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I rise to oppose this Bill. Even in democracy, for smooth running of the Government, certain restrictions must be there on Government machinery. My hon. friend has cited certain examples of removal of some people during emergency, but as we know now, because of the constitutional amendments, emergency will not be applied in the country except in remote circumstances. Therefore, to argue that in such contingencies these Articles are likely to be misused and that is why these should be removed is not correct. Secondly, the trade unions, industries, their employees and employers relations—all these should not be mixed up with the Government and the Government employees.

My hon. friend has tried to say that the Governor or the President does not have the direct knowledge of the person who is to be removed from service under these Articles. But we must not forget that the clever Government servants continue to remain in

service on account of the mistakes committed by their superiors in removing them and taking advantage of the delay in the judicial processes. Despite the fact that they are not fit to remain in service, because of these reasons, they still remain in service. Even after an enquiry is held, there are three or four types of punishments like removal, dismissal, termination from service etc. All these terms come into play when the suit is instituted in a court of law, and a number of employees come back. Several persons came with representations that they were removed during emergency because they did not obey the orders of the then so-called authoritarian Government but this Government has come to realise that most of these representations were not correct. These persons were removed because of their misbehaviour or some other crimes. It was also because of their corruption and other things. So, just taking the example of Emergency and asking for the removal of Articles 310 and 311(2)(c) will not be proper. Article 311 (2)(c) says:

"Where the President or the Governor, as the case may be, is satisfied that in the interest of security of the State, it is not expedient to hold such enquiry...."

We find that in many cases, the man needs to be removed instantly. He commits such crimes that a *prima facie* case exists for his dismissal on the spot. But if these Articles are removed, Government will not have any machinery whereby it can control the miscreants. We have seen that though Government servants are not expected to take part in politics, on many occasions they do take an active part in it. We see the Government servants in cooperative movements, and standing for elections therein, without taking the permission of the higher authorities. So many things are done; and if a person is suspended, after 2 or 3 years, in 95 per cent of the cases he comes back and is reinstated. Often it is said that suspension is a compulsory rest. In other processes of

removal from service of miscreants, even though a man may be guilty, the machinery or the process is very defective. With that point in view, I would say that the Articles which were introduced in the Constitution, viz. 310 and 311(2)(c) are appropriate. It is not just good to say that they have come to us from the days of Victoria, and we are continuing them. Many people have observed the pros and cons of these Articles, during the 30 years after our independence. The Emergency is now over. So, just introducing the Bill for removal of these Articles at this stage is not proper. We have seen that in autonomous bodies like universities and others which are sponsored by Government, sometimes the unions gherao the Vice Chancellors and others. It happens in the factories also. We are thinking of introducing an Industrial Relations Bill applicable to factories also. A poor manager is gheraoed by many employees. His life is threatened. There also, we are trying to introduce some restrictions, through the Industrial Relations Bill, so that punishment can be accorded to the man who gheraos.

Here, in Government, these powers which are vested under Articles 310 and 311(2)(c) are very seldom used. So, I oppose the Bill.

SHRI VINODHBHAI B. SHETH (Jamnagar): Mr. Deputy Speaker, Sir, The Bill is a very important one and the statement of objects and reasons look very laudable, in the first instance, just to protect them from any arbitrary or undue harassment from the highest authority. We have learnt something from our past experience, particularly during the emergency. In any part of the democratic world, opportunities must be given to the aggrieved person. I would like to add that the officers should not feel that they do not get protection from the Government. And the Government machinery should run in such a way that due justice should be given to the aggrieved party. Here the aggrieved party may come from the village. He may be an uneducated

citizen. He may be an officer or he may be a Member of Parliament. Unfortunately, I had spoken in this House that even a Member of Parliament's voice is not heard in the lobby. I am sorry, being a member of my own party, to express such a view. But, some-how or the other, the machinery of the Government has been running, right from the very beginning when the British raj was here in this country, in the same pattern. The same red tapism is there. So, I would like to give one more suggestion that we can give protection to the bureaucrats, but they should behave in such a way that they are responsible to the public through the Members of Parliament.

If the Supreme Court or the High Court has passed a strict remark against some of the decisions arrived at by the officers, then an enquiry should be instituted even against the officers why they misguided the Minister. One of the yesterday's leading bureaucrats has become a lord of this country.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: Class III and Class IV employees are affected.

SHRI VINODHBHAI B. SHETH: They cannot express their will. One very senior national leader has said that our Ministers have become simply a signing machine. They sign papers without reading them. They do not apply their mind and hence the bureaucrats have got an upper hand in this country I can cite many examples. In Gujarat, one Headmaster had burnt the education officer alive. He was complaining for many years about some of the problems over which Government machinery did not pay attention. Therefore, he took this decision of burning the education officer alive. This shows that the voice of the common man, a small person should be channelised through the elected representatives to the Government machinery; and the Government machinery should be responsible, should be vigilant should be quick and efficient in meeting the needs of the people.

[Shri Vinodbhai B Sheth]
16.13 hrs.

[SHRI N. K. SHEJWALKAR in the Chair]

Thirdly, the entire machinery of the Government needs some changes. Now the old machinery of the Government has to give way to the new orientation, because everybody feels—wherever we go, either we travel by railway or plane—that nobody is happy with the administration which we are having, which is a legacy of the British raj. Let us think afresh, let us go ahead and see that the popular will of the people is respected. They have elected us. We are not here to just say, 'Ayes' and 'Noes' in respect of a particular Bill. We have been elected here in this House by the people to give vent to their feelings and protection should be given to everybody. I can quote so many examples here in this respect. As an elected representative, I can say that no justice has been done to these people. We wrote so many letters to the Ministers and the Minister say, "You are right", but the officers do not agree with these views of the Ministers. But I am sorry to say that our Government officers should not go against the views of the Minister. They should apply their mind. If we are right, they should tell us that we are right; if we are wrong, they should also tell us that we are wrong.

I would like to make one more suggestion. There should be a permanent complaints cell to receive complaints and then to forward them to various Ministries to come to an amicable settlement. In the states and the centre, complaints cell has now become necessary. Otherwise there are so many copies of letters addressed to the Prime Minister and Ministers and others; it is all an unnecessary exercise. I request the Ministers concerned through you to pay proper attention to the letters received from Members of Parliament and other elected representatives of any association and to apply their mind and give weightage to them because the janata, people

who elected us, want us to be efficient in administration, quick and honest. We want not only honest administrations but efficient and honest administrators. A man in the remote village could see his wish fulfilled through the officers if they are honest and efficient; the government machinery and the officers can get direction through this august House.

SHRI DHIRENDRANATH BASU (Katwa): I am speaking in support of the Bill. I am surprised that some of my friends were opposing the Bill. To oppose a Bill like this is to support the same process as the Emergency. In this Bill it will be seen that some of the fundamental rights have been taken away. The statutes provide that a government employee is in service at the pleasure of the Governor or other authority and can be dismissed from service without assigning any reason whatsoever as soon as the pleasure of the governor or the pleasure of the authority goes. Now the governors do not exercise their powers as the powers are being exercised by the bureaucracy, officers, who are often times junior IAS officers, SDOs and others. So, the service of these servants depends upon the pleasure of those people. If those officers choose they can dismiss him without assigning any reason whatsoever. So this article 310 should be deleted; amendment to article 311 is also necessary. Under article 311, no person who is a member of the civil service of the union or all India service or the civil service of a state shall be dismissed or removed by an authority subordinate to that by which he was appointed. In a democratic set up trade union activities must be retained. If there are no trade union activities how can we say that we are a democratic country. So our Constitution should be framed in such a manner that the present democratic set up, as envisaged two years back, should be retained under all circumstances to serve the interest of the people. Clauses are here in this particular Article. It will be seen that the employees will have no right to

exercise their union activities. In all democratic countries of the world union activities are always welcomed. It is rather easier to tackle the leaders of the union than to tackle the individuals. So unions and the trade union activities are always encouraged in all democratic countries of the world. Now in a Socialist Democratic Republic like ours in India I wonder how the Minister could retain such Articles in the Constitution.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE:
How can the Minister oppose this Bill?

SHRI DHIRENDRANATH BASU:
It will be in the fitness of things that the Government should accept the Bill. The Government should come forward. So, I request through you that the hon. Minister may accept this Bill. It is a democratic step. It is for the welfare of the employees. It is for the benefit of the people. This Bill should be accepted as it is.

SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN (Coimbatore): I rise not only to support this Bill whole heartedly, but also with a sense of what shall I say confidence that the smiling Minister who sits there should accept this. This is the confidence that I have because he also participated in the movement for freedom. When we participated in the movement for freedom, we wished to throw away all the shackles and vestiges of the imperialists. Here is the last shackle that is there in the Constitution.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE:
There are other shackles also.

SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN: Yes, many other shackles are there. For instance Railways Act, etc. are there. Any way, this is an important one. I can hear the Minister saying—it is not directed towards trade union activity. This is for misconduct. Where you find that the employees are anti-national, anti-Government or guilty of serious misdemeanour, this is the way that it is

covered up. But if you look at its history the power has been used precisely against government employees—clauses 3 and 4 at the time of strike or during any trade union activity are used. If you look back when the Central Government employees strike took place in 1963, when Railway strike took place in 1974, this was freely used. And what happened. After the union moved, they were taken back. Then how are they anti-national? The point I wish to make is that this is a totally undemocratic clause in the Constitution.

Even during the emergency when the 42nd Constitution Amendment Bill was being discussed, we fought for removal of this. Again when we had the Constitutional Amendment Bill set right misdemeanour and wrong actions of the emergency period and when the Constitution Amendment Bill was being discussed, we demanded that this should be removed from the Constitution. Why did we do it. It is very simple. All that we demand is that Government employees irrespective of their misdemeanour should have the right of appeal and cannot be just summarily thrown out on the streets because of the mere whims and fancies of some superior officers who may well be paying off their old scores. Whenever we have been strong enough to move and to point out that this was nothing but paying off some old scores or because of anti-trade union activity, when we have been able to secure reinstatement. This itself is the most telling fact how many have been reinstated is the most telling fact.

This is something that really should not remain there. After all, there are enough measures in both private sector and public sector undertakings to deal with difficult employees. In public sector undertakings if there is any employee who really is anti-national, who is really acting against the interest of the particular enterprise, there is enough in labour legislation to guarantee that action can be taken

[Smt. Parvathi Krishnan]

against him, while at the same time giving him every opportunity to defend himself. That is all that we are asking for. The Central Government employees are at your mercy.

I know many cases where a Central Government employee is called upon by his higher officer to do something which does not fall within the purview of his assignment or what he is supposed to do, he is often threatened by the officer saying, "Remember, I can always see that you are out on the streets!" This is the kind of Draconian power that is there with the higher officers. It is not the President who exercises it. It is under the President's order no doubt and therefore, there is not even the right of appeal that a condemned prisoner can have.

A prisoner who is condemned to death can send an appeal to the President asking for communication of the sentence. But here a Government employee who is thrown out on the streets under this article has no right of appeal anywhere. He is out once and for all. See how absolutely antihuman the whole thing is. It is only Victorian England that could think of a thing like that. Here we are in 1979, 32 years after freedom, clinging to these Victorian ideas and descending—I hope he is not going to descend—to the Victorian concept of hire and fire at the whim and fancy of the employer.

Throughout the world employers and industrial workers have fought and achieved these trade union rights. We have done it in our country also. Here comes my friend, Shrimati Renuka Barkataki. She is very concerned with the rights of women workers, particularly rural women workers and rightly so. She is concerned with trade union rights of employees and she says, "why don't you train women to take on responsibility?" May I tell her that when we are willing to train them to take on further responsibilities, they hold back. They

are not sure. Their mothers-in-law threaten them. People at home threaten them saying, "don't go. You will lose your job. Articles 310 and 311 are there, which can be used against you." Similarly we have heard complaints from women employees in Central Government who have told us how senior officers try to take undue advantage of the fact that they are women and they are also threatened in the same way. There are a million ways in which this is misused. It is the fundamental right of any human being in India in 1979 to have the right to appeal always against a decision which goes against him or her which he or she knows is unfair and get proper redress. That is why I whole-heartedly support this Bill.

Those who are sitting in the treasury benches today came to power, having stood in 1977 elections, on one slogan: Restoration of democratic principles in this country. The previous Prime Minister came to power in 1971 on one slogan: Garibi hatao. Since she did not hatao garibi, she was hataoed. You came to power on the slogan of restoration of democracy. Yet in the case of loco running staff who have been demanding that their grievances which have been pending for years and years should be discussed, article 311 has been used against some members of their association in the N.E. Railway, S.E. Railway and Southern Railway.

What has happened to the ticket checking staff who have also taken up their demands? Against them also, the same rule has been used. We go to the Railway Minister, who is a great champion of democracy, and what does he say? He says: "If I get reports about any single worker that he is working against the interest of the Railways, I will see that he is out." This is what he said in personal talks with us when he represented particularly this thing to him.

All right, if you think that the Railway workers' concerned have been, in a way, indisciplined or their

work has been affected, the usual discipline and appeal rules are there. Many other procedures are there. The unions are there to pull them up because we, trade unionists, are responsible people. While we fight for the workers' rights, we also tell the workers what their responsibility is towards their job. But how can the wooden-headed bureaucrats get you to understand that because they have neither the responsibility towards their job nor they fight for the down-trodden and Class III and Class IV employees. Otherwise, we would not have 1.8 lakh casual workers still continuing on the Railways; we would not have come here again and again and asked for protection for the extra-departmental staff of the postal services and we certainly would not have a position where our telephone operators are not even given proper conditions while they are on night duty or given transport to go home or given canteen facilities. These wooden-headed bureaucrats whom the Minister will be defending shortly as appears from the smile that he has on his face, do not know what are democratic rights, what are democratic principles and what is real democracy.

It is in the name of real democracy that I demand from the Minister that he should accept the Bill that has been brought forward by my young friend, Shri Bhagat Ram. He was himself a teacher. He knows very well how his power can be mis-used, is misused and is always directed only against the Class III and Class IV employees and invariably when trade union activities are involved. Therefore, when you claim that you are responsible for restoring democratic rights, remember, your job is not over. Otherwise, as the lady of 'Garibi Hatao' was hataoed, be careful, you also will be hataoed.

श्री राघवजी (विदिशा) : समापन जी, श्री भगत राम जी ने जो संविधान संशोधन विधेयक यहाँ पर पेश किया है उसका समर्थन करना सम्भव प्रतीत नहीं होता है। उन्होंने कहा है कि संविधान की धारा 310 का दुरुपयोग हो रहा है तो मैं यह जरूर कहूँगा कि धारा 310

का दुरुपयोग पूर्व में हुआ है और आगे भी हो सकता है। आपातकाल में इसका जो दुरुपयोग हुआ वह मदन के माननीय सदस्यों से छिपा नहीं है। लेकिन अगर धारा 310 हटा दी जाये तो अद्वैत अधिकारी और कर्मचारी इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। एक तरह से यह एक दुबारी तलवार है। अगर किसी अच्छे श्रमी मजदूर ध्यवित के हाथ में है, जिसकी भावना अच्छी है तो वह मुरझा की भावना पैदा कर सकता है सारे समाज में और अगर वही तलवार किसी गुच्छे या डाक के हाथ में है तो वह उसमें एक आनक वा भाव पैदा कर सकता है। इसीलिए प्रश्न यह है कि इसका उपयोग किस प्रकार में किया जाता है, मारी बात इसी पर निर्भर करती है। टमजंम्मा के दिनों में जो टमका दुरुपयोग किया गया उस समय मारी मला धीमती इन्दिरा गांधी के हाथ में थी और जानबूझ कर उस समय इसका दुरुपयोग किया गया। परम्परा यह है कि टम प्रकार के अधिकारों का उपयोग बहुत कम अवसरों पर होता चाहिए। जहाँ बहुत आवश्यक हो वहाँ पर टमका प्रयोग होता चाहिए। यही धारा 310 का भावना है कि क्योंकि धारा 310 के बाद धारा 311 दी गई है और इस धारा 311 में कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा की गई है। टम धारा में इस बात का उल्लेख है कि किसी भी कर्मचारी को भव तक नहीं हटाया जायेगा, जब तक उसका चार्ज नहीं दिया जायेगा, जब तक उस पर जा दोग लगाये गये हैं उनका जांच नहीं हो जायेगी, जब तक वे दोग सिद्ध नहीं हो जायेंगे तब तक उनका नहीं हटाया जायेगा। अगर धारा 310 का टटा दिया जाये तो कर्मचारी और अधिकारी दोनों उसका दुरुपयोग कर सकते हैं और उस समय बड़ी कठिन परिस्थिति पैदा हो जायेगी।

इन्स्ट्रुमन्ट में बहुत सी ऐसी सेवाये हैं, यदि उन के कर्मचारियों पर नियंत्रण नहीं रखा जाये तो तमाम देश बरबाद हो जाने पर जोर मरना है, जैसे मेला की सेवाये हैं गार्डन की सेवाये हैं, बिजली विभाग में काम करने वाले कर्मचारी हैं मल-विभाग में काम करने वाले कर्मचारी हैं। ये ऐसी सेवाये हैं जिनसे जन-जीवन प्रभावित हो सकता है, जिनसे देश की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है, समाज की शान्ति प्रभावित हो सकती है। ऐसी सेवाया का संचालन करना जिन के हाथ में है, यदि वे ऐसा गमज में कि हम का काट्ट नहीं टटा सकता, और वे इन्स्ट्रुमन्ट पर चले जाये तो हम से समाज को नुकसान होगा, समाज प्रभावित होगा, उसका परिणाम बिधा जा सकता है। हमने इस समय इस पर प्रकाश डालने देखी है—जब पूरी यातायात व्यवस्था ध्वंस कर दी गई, जन-जीवन अत्यन्त कष्ट दिया गया, यहाँ तक कि जो बीमार थे, उनको अस्पताल तक नहीं पहुँचाया जा सका। अगर बिजली कर्मचारी इन्स्ट्रुमन्ट कर देते हैं तो हजारों नहीं, लाखों लोगों का जीवन नरक के समान हो जाता है, चारों तरफ अंधकार छा जाता है। यदि पानी कर्मचारी इन्स्ट्रुमन्ट कर देते हैं तो समाज का पानी नहीं मिल पाता है। यदि उनको मारो तो नरक ध्यान दिया जाय, तो ऐसा मालूम पड़ता है कि उनमें कीड़े चाद साँगों का हाथ है, वे ऐसी इन्स्ट्रुमन्ट कर कर अपनी मोटी बैटना चलाते हैं, जन-जीवन के साथ खिलवाड़

[श्री श्यामजी]

कर के उम मक्ति का दुर्ूपयोग करना चाहते हैं। इसी तरह से यदि देशद्रोही कर्मचारी भी दुर्ूपयोग करना चाहें तो देश की रक्षा करना बहुत कठिन हो जाता है।

मैं मानता हूँ कि इस में राष्ट्रपति और राज्यपाल को अधिकार दिये गये हैं—राष्ट्रपति या राज्यपाल के प्लेजर का प्रावोजन है, लेकिन इस के साथ साथ यदि यहाँ पर कोई मफ-गार्ड रखता है कि गट्ट, विन किन परिस्थितिया में इन का उपयोग कर सकता है—ता भी इस बात का स्वीकार कर सकता है। मैं मानता हूँ कि इस का दुर्ूपयोग भी बहुत जगहों पर हुआ है न्यायप्रिय कर्मचारियों को बहुत तग किया गया है, मनाया गया है। मैं ऐसे ही चार उदाहरण आप के सामने रखना चाहता हूँ—क्योकि यह बात भी सामने आनी चाहिये कि किस प्रकार स अधिकारी नीचे के लोगों का सताते हैं। उनको तग करते हैं, उन का ठीक से न्याय नहीं देने हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ धारा 310 का प्रयोग जाना चाहिये। सीधाय से हमारी राज्य शिक्षा मंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं—मैं विशेष रूप में उन को बलवाना चाहता हूँ कि मथुरा में एक हरिजन अध्यापक ने अपने ऊपर नैन छिड़क कर आत्म-हत्या कर ली। उस के पीछे कारण यह था कि वह तीन वर्षों से लगातार अपनी सेवाओं के बारे में प्रिन्सिपल को लिखता रहा, लेकिन उस की समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया। उस ने बार-बार लिखा, अनेक बार स्वयं मिला, लेकिन प्रिन्सिपल ने उस की बातों को नरफ ध्यान देने के बजाय, उस का दुनकाग, उसका प्रनारणा दी और अन्त में उस ने परेशान हो कर आत्म-हत्या कर ली और यह प्रिन्सिपल वह ज्यति या जिम के खिलाफ सी० बी० आई० की एम्बवायरी चल रही थी, जो हाल ही में ट्रांसफर हो कर मथुरा माया था। इस की जांच हानी चाहिये। आत्र उम गरंज हरिजन अध्यापक का परिवार मडप रहा है।

इसी तरह से नेगा नगर में पब्लिक अडवर्टाइज है। वहाँ का प्रिन्सिपल भी ठीक इसी प्रकार स अपने अधीनस्थ अध्यापकों का तग कर रहा है। वहाँ का महिला अध्यापक है उन का रात को 9 और 10 बजे तक राके रखना है। और उन का तरह तरह में तग रगना है, ह्युमिनियेट करना है। उन के साथ अपमानजनक और अमानवीय बात बरता है। वहाँ का एक अध्यापक और है जिसको इनना तग किया गया कि वह आत्रबल अस्पाना में मर्ती है और उसकी व की भी मोन हो सकनी है। इस तरह से अध्यापकों के साथ वहाँ व्यवहार किया जा रहा है।

मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूँ। धारकेलाजिकल सर्वे आफ इंडिया के एक कर्मचारी श्री पाटनकर जो कि भोपाल में नियुक्त थे, उन के परिवार वाला और जिलाधीश के रिश्तेदारों के बीच किसी झगडे के कारण श्री पाटनकर के खिलाफ एक मूठा केस बनाया गया और उनको मीसा के अन्दर बन्द किया गया। उनको 13 महीने तक जेल में रखा गया, उन का नौकरी से हटा दिया गया। यह स्थिति यहाँ तक आ गयी कि जब एमर्जेन्सी खत्मत हुई तो रस्तोगी प्रायोग के सामने

उनके बयान हुए तो अधिकारियों का यह बात पसब नहीं आयी। उन का संस्थान तो पहले ही खत्म हो चुका था लेकिन उनके बयान के बाद उन्हें भोपाल से पटना ट्रांसफर कर दिया गया। भोपाल में उनकी पत्नी काम करती है लेकिन उनका ट्रांसफर पटना कर दिया गया। सभापति महोदय आप जानते हैं कि इस प्रकार सामकीय आदिश है कि जहाँ पर कसी कर्मचारी की पत्नी काम करती हो ता उसी स्थान पर कर्मचारी को रखन की व्यवस्था हो। लेकिन एमर्जेन्सी हटने के बाद और जनता सरकार के आने के बाद उनका भोपाल से पटना ट्रांसफर कर दिया गया। उन पर भोपाल में केस चल रहा है और उनको हर दूसरे महीने भोपाल आना पडता है और तीन सौ रुपया धरनी जब से भोपाल आने जाने में खर्च करना पडता है। लेकिन जा व्योन्टे नोग है वे इस बात को नहीं देख रहे हैं। विभागीय अधिकारी यह समझते हैं कि वे उनका वमजोरियों का सूचना मगदु सदस्या को देते हैं, इमार्लाग उनका यह मजा दी जाए। ऐसे उदाहरणा को कमी नहीं है। मैं चाहना हूँ कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ मविधान की धारा 310 का अवश्यक प्रयोग किया जाए और उनमें अधीन ऐसे अधिकारियों को दण्डित किया जाए। ऐसे अधिकारियों को दण्डित करने में यह धारा 310 कादान मिड हो सकनी है। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ एम को बरदान स्वकप मानना चाहिये और इस का उपयोग किया जाना चाहिये इमनिये यह धारा सविधान में बहुत अवश्यक है।

सभापति जी, मैं एक दा बातें और करना चाहता हूँ। हमारे हिन्दुस्तान के अन्दर जिनन भी सामकीय विभाग है, चाहे व केन्द्रीय सरकार के हो, चाहे वे राज्य सरकार के हो, चाहे सार्वजनिक प्रतिष्ठान हो, चाहे ऐसी संस्थाएँ हो जिनका सरकार से अनुदान मिलता है, इन गमी में लाखों कर्मारी टम्प्यारेरी बर्सेस के रूप में कार्य कर रहे हैं। इन सभी संस्थाओं में कर्मचारिय, बा दो वर्षों की टम्प्यारेरी सेवा के बाद परमानेंट किया जाना चाहिये। मैं ऐसे भी उदाहरण दे सकता हूँ कि कर्मचारी टम्प्यार होने वाल हैं, लेकिन टम्प्यारेरी ही चल रह है, उन को परमानेंट नहीं किया गया है। मैं चाहता हूँ कि इस कर्मचारी को उन के दो साल के अछ्ठी रिवाड का देख कर उनको दो-माल को सेवा अछ्ठी देख कर परमानेंट कर दिया जाना चाहिये। टम्प्यारेरी कर्मचारियों के खिलाफ अधिकारी लाग मनमानी करते हैं। एमे कर्मचारी हिन्दुस्तान के एक अधीन विभाग में नहीं हैं बरि-कमगम सभी विभाग में हैं और उन की मख्या लाखों में है। मैं कहना चाहता हूँ कि इस के बारे में निगियन रूप से नियम बनाये जाने चाहिये कि अगर किसी ने माल भर काम कर लिया है और उस के खिलाफ कोई बात नहीं पाई गई है और उस को किसी बान के बारे में कुछ नहीं कहा गया है ता उस का परमानेंट कर लिया जाना चाहिये। अगर इस प्रकार के नियम नहीं बनाये तो सीस तीस सान से टम्प्यारेरी रूप में कार्य कर रहे हैं उनका भला नहीं हो सकेगा। इस बारे में ठोम नियम बनाये जाने चाहिये।

सभापति महोदय, हिन्दुस्तान भर में कैजुअल बर्सेस काम कर रहे हैं डेली बेजिज पर काम कर रहे हैं ? उन को भी प्रोटक्शन मिलना चाहिये। उनको कैजुअल

बर्कर के रूप में खड़ा जाना कब तक चलेगा ? उन को 11 महीने काम पर रखने के बाद 1 महीने के लिए हटा दिया जाता है फिर उन्हें रखा लिया जाता है । उन को भी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिये । केजुवाल बर्करों, डेली बर्करों, टम्परेरी बर्करों से जितने हैं उन का सविधान में जरूर कुछ न कुछ सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिये । यह सब हानि के बाव कर्मचारियों को ठीक रखा जा सकता है । जहां तक धारा 310 का सम्बन्ध है इस का उपयोग किस रूप में होना चाहिये यह विशेष महत्व की बात है । इस का इस्तेमाल कर्मचारियों की भलाई के लिये भी हो सकता है और बुराई के लिये भी हो सकता है । लेकिन हम धारा का शायद के पास बने रहना बहुत आवश्यक है । अगर इस का सदुपयोग किया जाय तो यह धारा देश के लिए बरदान सिद्ध हो सकती है ।

इन शब्दों के साथ मैं हम सभाकम विधेयक का विरोध करता हूँ ।

SHRI P SHIV SHANKAR (Secunderabad). Mr. Chairman, Sir the Bill deals with two Articles. Firstly it deals with the deletion of Article 310 and secondly with the deletion of Article 311(2)(c). So far as the second clause of the Bill is concerned, that relates to the deletion of Article 310 and Clause 2 Part (c) of Article 311 is dealt with in Clause 3 of this Bill. As far as I am concerned, I am only sorry. I am not able to agree with the mover of the Bill so far as Clause 2 is concerned, but I entirely agree with him so far as Clause 3 is concerned and to that extent, I am supporting the Bill. That portion of the article should be deleted. The founding fathers of the Constitution thought it fit, to give the constitutional status to the services of the Government servants. Once they have been so kind to the Government servants to place them in such a hiatus, the question that arises with reference to this Bill is, what is wrong with Article 310. I am not able to understand the grievance because I personally felt that there is something wrong with the drafting part of the Bill, may be that Mr. Somnath Chatterjee's legal advice was not available to my friend, who has moved the Bill.

If you kindly consider Article 310, it deals with the pleasure doctrine. A person who holds a civil post, 4652 LE—13.

would hold that post during the pleasure of the Governor or the President as the case may be. But what is to be seen is that Article 310 commences with the words "Except as expressly provided by this Constitution". These are the relevant expressions. When once there is something which is provided by this Constitution, the absolute pleasure doctrine that one would conceive is totally negated. Therefore, if you kindly see Article 311, in case of dismissal, removal or reduction in rank, it is only the appointing authority who has got the power, and this action cannot be resorted to unless a reasonable opportunity is afforded to the aggrieved person. This is simply, I must submit, the incorporation or bodily lifting of what one would call the principles of natural justice. When we look to Article 310, as I submitted, it starts with the words "Except as expressly provided by this Constitution". Now Article 311 provides that a reasonable opportunity should be given to a Government servant if he is to be dismissed, removed or reduced in rank. Therefore, I am not able to appreciate as to why the deletion of Article 310 has been sought in the Bill. The pleasure doctrine is not that absolute as to say that it is not hedged by any other consideration. I should submit that this pleasure doctrine which has been engrafted in article 310 is subject to article 311. Therefore, if a particular person has to be removed or dismissed or reduced in rank, you cannot do that because article 311 itself says, firstly, the appointing authority has got the power and, secondly, such a person has to be given a reasonable opportunity.

I would rather submit, as to why this pleasure doctrine has been engrafted with reference to the President and the Governor alone. We are well aware that the entire executive action of the Government which is exercised under article 162 of the Constitution has got to be expressed in the name of the Governor, if it is a State and, in the name of the

[Shri P. Shiv Shanker]

President, if it is the Central Government. That apart, it is the Governor or the President in the respective spheres who make the rules under article 163 of the Constitution for the purpose of discharging functions and better administration of the Government. Well, constitutionally it is supposed that the Governor or the President is the sole repository and the head of the services inasmuch as every action of the State Government or the Central Government is expressed in the name of either the Governor or the President as the case may be. Therefore, under article 310, the pleasure doctrine has been enshrined and this expression has been used "as to the pleasure of the Governor or the pleasure of the President except as expressly provided" so as to make the things effectively clear.

I submit that this is clearly a point of the constitutional scheme. I have not been able to appreciate as to why article 310 is sought to be deleted. I am only sorry, that I am not able to appreciate so far as this part of the Bill is concerned.

In fact, I was sometimes back going through the debates of the Constituent Assembly about the discussion on clause 282A which is synonymous to article 310. Questions were raised with reference to pleasure doctrine and it was clarified that this pleasure doctrine could not be isolated and that it has to be read in conjunction with the other provisions. I would not like to dilate on this aspect because I am not very sure whether the mover of the Bill himself has carefully considered this aspect.

SHRI VAYALAR RAVI: The point is, what is the effect of this clause and later how it will be implemented.

SHRI P. SHANKER: I would rather say, left to myself, the matter of services need not have been put in the apparatus of the Constitution. The matters pertaining to services could be totally relegated to the law

of the legislature as it is clearly enunciated in article 309 itself. I would not like to go into that. For the present, I am more concerned with the amendment of the Constitution that has been brought by my hon. friend and I would rather say that if he would like to delete article 310, the whole scheme of the Constitution gets affected and, therefore, I am opposed to that extent.

Now, I go to article 311 (2) (c). I am only sorry, perhaps the legal advice of Mr. Somnath Chatterjee was not made available. I should say, so far as the mover of the Bill is concerned, if he is finding fault with article 311 (2) (c), there is something equally wrong with article 311 (2) (b) and also article 311 (3) and if they have to go they must go lock, stock and barrel. I must say that this provision had been a highly controversial one. If I correctly recall, the Supreme Court had to consider this in Sardarilal's case, in 1971. The Supreme Court while considering this said that Once the State takes action under article 311 (2) (c), it was not open for the court to further investigate into the matter.

No doubt, at a later stage, they slightly diluted it—I quite concede that the expression 'security of State' is undoubtedly very dear to the heart, but this expression can certainly be exploited. Why I say this is. No doubt, the theory of jurisprudence, in the administrative law is that there is nothing wrong in reposing the discretionary power in responsible authorities and, it is expected of that authority whether to exercise that power or not in a given situation. It is obvious that the more powerful a person is or more highly-placed, when it comes to the question of exercising the power, he must be more restrained and careful. Why I am supporting this part of the amendment is because there is a likelihood of misuse. Here it is said:

"...where the President or the Governor, as the case may be, is

satisfied that in the interest of the security of the State it is not expedient to hold such inquiry."

It is purely a subjective satisfaction of the Government, and that subjective satisfaction is that, in the interest of the security of the State, it is not expedient to hold inquiry. Well, what I am submitting is that. The expression 'security of State' may be very much dear to the heart, but it can also be very much exploited. What is 'security of State' is a very nubulous expression; In fact, it is not possible to define it. Suppose on a subjective satisfaction the Government or the President comes to the conclusion about an innocent man. 'Here is a person whom I dismiss or remove, but nonetheless I will say that, in the interest of the security of the State, it is not expedient to hold an inquiry', then it is obvious that an injustice is extended to such a person. After all, what we thought or believed in our Constitutional goal? We want to usher in, what is called, a Socialist, Democratic, Secular Republic. The principles of liberty, the principles of democracy, the principles of social, justice and equality are enshrined in our Constitution. The question is this. What is wrong, if you give a chance to the person, who is dismissed on the ground which falls under article 311 (2) (c), telling him: 'Look, these are the charges on which I would like to take disciplinary action against you and, therefore, you explain'. To say that merely because a particular authority thinks that security of the State is involved, it is not expedient to hold such an inquiry, is too unjust an approach. I would not be able to give a political tinge to the argument as my predecessors have done because I am a novice to politics. My approach is purely legalistic. I am arguing as a lawyer, as a common man, as a citizen of this country. When it comes to the question of taking action under article 311 (2) (c), I am only sorry, that it is fraught with dangerous consequences, and I submit, there is

nothing wrong in giving a chance to the person concerned. I get reminded of one judgment of the Supreme Court. The Supreme Court, as far back as 1967, in Roshan Lal's case observed that, so far as Government service is concerned, once an offer is made and the person concerned has accepted, it is no more a question of a contract, and the service is a matter of status governed by the statutory rules, once this is the approach, and you are taking the position other than that of a contract you are pitching the employee to a position or claim as to status then he cannot be dealt with otherwise. Then the statutory rules framed within the meaning of the proviso to Art 309 or the law that the legislature had framed under the main part of Art 309. Then my submission is: what is wrong in giving a chance to that person within the meaning of the Conduct Rules or within the meaning of the disciplinary rules, to give a chance to him apprising. 'Look. Your activities are contrary to the security of the State. Therefore, I would like to take disciplinary action and meet out the punishment proposed.' You can specify those matters to him so that that man may have a reasonable opportunity to express himself and on that basis the authority could come to his own conclusion. Therefore, what I am submitting is: why to deny such a person even the basic right of being heard which is most important. Now it is accepted that whether you have a rule or you do not have a rule, whether you have a law or you do not have a law, so far as the principles of natural justice are concerned, the principle as to *audi alteram partem* could not be denied before acting to the prejudice of a person. This is the principle which is applicable to all types of actions which the authority resorts to, either under the administrative jurisprudence or otherwise.

Here I get reminded of the declaration Magna Carta in England where they said that nobody should be condemned without being heard. There-

[Shri P. Shiv Shanker]

fore, what I am trying to say is that this particular clause is really abnoxious. There is a likelihood of some mischief if some one acts even with a little negligence and because of that likelihood, I am in favour of this part of the Bill. Though it might be used sparingly and for very good causes, but the fact remains that it is liable to be misused—and it is from that point of view I am supporting clause 3 of the Bill. I am however only sorry that the mover of the Bill has not taken into consideration sub-clause (b) of clause 2 of Art 311 as also clause (3) thereof because they go together. I regret that we have come to a state of affairs in the Bill where something has been left. I would rather say, supposing this particular Bill is passed, with reference to sub-clause (c) of Article 311(2), the authority can have recourse to clause 311 (2) (b) read with (3) and then create difficulty. I am finding myself in a very anomalous situation so far as this clause is concerned...

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: Although whatever is proposed you support.

SHRI P. SHIVA SHANKER: In fact I would rather request Mr. Bhagat Ram—in which case I would certainly support him—to come forth with the other amendment to delete sub-clause (b) as also clause (3) so that his intention becomes completely clear and the democratic process so far as the services are concerned, may have a complete sway.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (Jadavpur): I must congratulate our young friend, Shri Bhagat Ram for bringing this Bill before the House and by which a very important point or problem is being highlighted before this august House.

Two Articles are sought to be amended. One is Art 310 and the other is Art 31(2)(c). Sir, if we go through the debates in the Constituent Assembly and even the judicial

expositions on these Articles in the Constitution of India, you will find that these are nothing but a replica of the Government of India Act of 1935 which was framed on the basis of the constitutional provisions or conventions in England where the theory is—it is a monarchy—that every government employee is a servant of the Queen or the King and as the King and Queen can do no wrong and there cannot be a contract of employment between the King and the Queen and the employee therefore, the employment must be at the pleasure of the Queen. That is the basis of a royal prerogative where there is no written Constitution although they follow the rule of law. There judicial determinations have tried to come to the aid of the government employees. But, here, we have a written Constitution Unfortunately, the concept of royal prerogative has crept into our Constitution. The misfortune further is that we now sit on the Treasury Benches, as King himself or the Queen

herself, His Majesty, Mr. S. D. Patil, to-day is still continuing to bear the notion that the Government employees are the servants in the sense that their services can be dispensed with at the pleasure or the power that be. Therefore, Sir, the time has come when this august body must repudiate once for all this concept of mediaeval feudal, royal or the barbaric concept that the Government employees in this country can be made to go on the streets and lose their jobs at the sweet will of the power; that are at the helm of affairs.

Sir, I know that Art. 311 was incorporated in the Constitution to put a check on that royal prerogative, the Crown's prerogative or the theory, at the pleasure of the Crown or at the pleasure of the Government. Under Art. 311, persons holding civil posts etc. that are mentioned here cannot be dismissed or removed from service or they cannot be reduced in rank without an enquiry being gone through in which they have to be given an opportunity, reasonable opportunity,

of defending themselves. As per the draconian Forty-second Amendment Act, the second opportunity should be given to the government employees against the so-called penalty proposal. They had two opportunities—one to show that they were not guilty or if they had been found guilty, they had been given an opportunity to make their representations on the quantum of punishment that may be imposed on them.

Now, the Forty-second Amendment did away with the second opportunity. The proviso to Art 311 of the Constitution, 311(2) of the Constitution lays down three cases where by not even an opportunity has to be given to show cause or with regard to the punishment/proposed. There are three cases - one is where the criminal court has found an employee guilty of certain offences. Let us take the case of misbehaviour, drunkenness or activities which are known as unbecoming of a government servant. There no criminal enquiry will be held because the rationale behind it is the competent criminal court where the government employee is an accused, he is given a full opportunity to establish his innocence or disprove his guilt. He need not be given an opportunity again to establish the same thing which the competent Court of law has done once. I can understand that a repetition to disprove the guilt may not be necessary.

The Supreme Court in 1974 has delivered a judgement which is an eye-opener for anybody. I do not know whether Mr Patil has been informed of this judgement in Chellappan's case where the Supreme Court has said that even when there is a recourse to proviso (a) to Art 311(2) (C) it is not necessary to establish the guilt. But he must be given an opportunity on the quantum of punishment imposed on him.

Therefore, although the enquiry is dispensed with, he must be given an opportunity to show that he should not be given the extreme punishment. Therefore, the principle of natural

justice has been invoked to make it a civilised provision of the Constitution. But, Sir, (b) and (c) provides where the administration thinks it is not reasonably practicable to give an opportunity, no opportunity need be given at all.

Sir, the railway strike has shown how grossly misused this provision of the Constitution can be. Rule 14(2) of the Railwaymen Disciplinary and Appeal Rule is the exact replica of 311 (2)(b) of the Constitution. Sixteen thousand employees, Sir, I had the honour to fight cases for them in Calcutta, Assam, Allahabad and Patna High Courts, we found except in once or two cases the government could not justify that it was reasonably not practicable to hold an inquiry. Notices were sent and notices came back with an endorsement that he is not available for some time. Although addresses are there in the offices and he could be easily served but on the plea that no service of a show-cause notice can be effected so dismissal orders were issued without an enquiry.

Mr Chairman, Sir, this is an uncivilised provision in the Constitution of India. According to me Articles 310 and 311 (2) and its proviso are nothing but blot on our Constitution such as, preventive detention provision; provision for imposition of emergency and provision for the imposition of President's rule without any guidelines, check and control. The moment these blots are removed we become a more civilised nation and can raise our heads high with the feeling that our Constitution maintains within itself the seeds of democracy. But these are the provisions which make a mockery of the Constitution and mockery of the democratic rights. Article 311(2) (b) is a pinnacle of unreasonableness in this country. I am challenging this government and any government to show one instance where Article 311 (2) (b) has been bonafide used. I can challenge this government cannot show a single instance. Previously, the misfortune was by judicial inter-

[Shri Somnath Chatterjee]

pretation it was held that exercise of power under Article 311 (2)(c) was not amenable to judicial intervention. It was held that this was not a matter which could be gone into by the court beyond the pail of judicial intervention. That was the position. Prior to 1971 it was being said: Why do you bother. Here the authority has been given to the highest functionaries of the State, namely, the President and the Governor. Therefore, these highest functionaries are expected to exercise their power bonafide and not malafide. It is not a petty bureaucrat who will exercise this power. On that basis Justice Grover in 1971 held that it is the President personally who has to go personally into the matter and decide the matter on his own without the help of the Minister or the help of the bureaucrats. That was the decision in 1971—Sardari Lal's case. That judgement has been over-ruled by a larger bench of the Supreme Court. Supreme Court has held in Shamsher Singh's case that it is not the President personally who has to take the decision or the Governor personally who has to take the decision. The decision will have to be taken by the Minister—political master—who either have not got the time or have not got the capacity to appreciate.

They are guided by the files unless they are themselves personally having some malafide intentions to put some Government employees in difficulties and so on. In that case it is well-established that it is the Government which has to take a decision, not the President or the Governor personally. First it was thought that the power to be exercised by the President or the Governor would be exercised on the application of their own mind uninfluenced by the decision of their political masters in this country or the bureaucracy. But that principle no longer holds good and the principle is well-established now in view of the Shamsher Singh's case of the Supreme Court. But here what does the order say? It says: 'In the interest of the security of the State, it is not desir-

able to have you; you are therefore dismissed with immediate effect.' I have seen so many of these orders. In 1969-70 the Second United Front Government came in West Bengal, was dismissed, or it came to an end and then there were a spate of dismissals under Art. 311(2)(a) of the Constitution. There was then an obliging Governor and he was prepared to sign on the dotted line, whether there was a report or no report. They obliged the Delhi authorities and Delhi was ruled by the then Prime Minister whose love for democracy is well-established and well-known. And in 1972 when the Siddhartha Shankar Ministry followed, there was again similar dismissal of State Government employees. I hoped that that would be the last such instance but then in 1975 when the emergency came what happened? Leaders of Government employees organisations were picked and chosen for being served with orders of dismissals. Actually 14 State Government employees were chosen for being dismissed. All of them were leaders and members of the employees' organisations. Mr. Chairman, you will be surprised to know this as a lawyer. I hope now even the Home Minister Mr. Patel retains some conscience. I would bring to your notice the incident where an employee of the Calcutta High Court was dismissed by the Governor under Art. 311(2)(c) of the Constitution. The Supreme Court held that the Governor had no such power to dismiss a High Court employee and that it is only the Chief Justice who can do it. There are rules with regard to the High Court employees' service conditions and so on. And when, as President of the High Court Employees' Union, I met the Chief Justice there, he said, 'what can I do, the Governor has passed this order, I can only endorse it.' But this employee lost his job. Sir, I had the honour to represent the Calcutta High Court Employees Union there and I filed a writ petition in the Calcutta High Court. The High Court held that the Governor had no power of dismissal of a High Court employee under Art. 311(2)(c) of the Constitu-

tion. This person was the Secretary of the High Court Employees Union. But the Governor arrogated to himself the power to dismiss this High Court Employee. And, Sir, I had the privilege of representing various other cases in the Calcutta High Court and in all these cases the Government could not produce a shred of evidence to justify that any security of State was involved. And in this connection I would like to mention one case of Mrinal Kanti Das Barman. Let the hon. Minister see for himself what was held in that case. The Calcutta High Court held there that the security of the State has to be given a meaning, anything and everything cannot be described as the security of the State, when the court calls upon the Government to show what was the security of the State involved. Supposing a Government employee beats his wife, they can write on the file that because the security of the State is involved, he is dismissed. Somebody beats his wife; that is not good, but what I am saying is that even on a fabricated charge that he is not behaving well with his or her spouse, a Government employee can lose his or her job on the plea of the security of the State. Luckily, the attitude of the Court has now changed. The court is now saying that it is a matter of judicial intervention; they are entitled to see what was security of the State involved, before the Government takes recourse to that. But it is not easy. You will appreciate, Sir, as a lawyer and other hon. Members will also appreciate that it is not easy to establish mala fide as such in a court proceedings. It is not easy because no body writes down on the file that he is mala fide doing this. Therefore, it is necessary that draconian provisions like this which have only be misused should be removed.

We know what happened during emergency, how the Central and other Government employees were dismissed. In Calcutta, the leaders of the employees were first detained under MISA. As they were detained under MISA, they were suspended. And because they were suspended on

account of detention under MISA, they were finally dismissed from service, because it related to the security of the State. How authoritarian it was! Was this civilised or the law of jungle that prevailed? I am appealing to the hon. Minister and all other friends of the Janata Party and others that this is a provision which is not necessary for a civilised administration anywhere or a bona fide administration anywhere.

It is said, sometimes there may be certain instances of misconduct where really the security of the State has to be protected, so immediate dismissal is necessary. There are ample methods of protecting the integrity and security of the country: suspend him immediately. If you think that he is acting against the integrity of the country, security of the country, even he can be arrested and a case can be started against him. But it should not be done without any proof, without any charge-sheet and without his having the satisfaction that he had some say in the matter that he was not guilty. At least give him that civilised opportunity to say that he was not guilty. Now, without an opportunity being afforded to him to say that he was not guilty, he is made to lose his job. Let an enquiry be made as quickly as possible to find out whether he is guilty or not.

Sir, this is a provision with in-built characteristics of high handedness and arbitrariness. It cannot be used for any bona fide object and it has not so far been used on a single occasion for a bona fide object. I would give a list of cases to the hon. Minister and particulars of the employees who were dismissed. The Calcutta High Court had set aside a number of such orders even during the emergency on the ground that these were mala fide. But, as I said, even High Court employees were not spared. Some people ask why this Article 310 is there, and why we are asking for its omission. We are asking for the omission of Article 310 because a very large section of Government employ-

[Shri Somnath Chatterjee]

yees have no protection under Article 311 of the Constitution. Those are in Defence Services—even civilians in Defence Services. We have seen that employees in Ordnance factories, civilian clerks, ordinary motor drivers, persons who have nothing to do with the actual fighting in a front, have been dismissed under Article 310 of the Constitution by this simple process, viz. by saying "You are in service under the pleasure of the Government. That pleasure is being withdrawn; and you are dismissed with immediate effect". It has held by the Supreme Court that because Article 311 does not apply, he is under the pleasure of the Government. So, once the pleasure is withdrawn, Article 310 comes in, and since Article 311 does not apply to them, so the pleasure doctrine applies. So, he is liable to be dismissed without any opportunity being given to him, without any enquiry and without any possibility of his proving his innocence.

I am appealing to my friends here, and to the Government. Is it the intention of the Government to have such provisions in our law, especially in the organic law of the country, viz. the Constitution, provisions which can be done away with easily, without any difficulty or problem for the State? Secondly, do we or do we not believe in the basic concept of democracy; and do we or do we not believe in a civilized system of Administration?

The basic postulate behind Article 311 is that the civil servants in the Administration, even the lowest rung of bureaucracy, should not be at the sweet mercy of the temporary political masters. That is the principle behind it. The principle is that the former are supposed, and expected to render service to the country, and to the Government irrespective of the colour of the Government that may be there. So, that protection has been enshrined in the Constitution of India, viz. that a temporary political master cannot tinker with their rights and

impose on them arbitrary penalties, and cannot interfere with the discharge of their duties—which should be done in a neutral manner.

The provisions under reference are those which strike at the root of this concept. I appeal to Government and everybody else here to realize that these are draconian provisions in the Constitution. Unfortunately, our Constitution contains many such provisions. You will recall that many of the provisions of the Constitution were sought to be amended by the Constitution, (45th Amendment) Bill. All of them could not get support in the Rajya Sabha. So, they could not be deleted from the Constitution.

There are many Articles of the Constitution which require much more than a second look. The opportunity has now come. My friend has at last succeeded in the ballot, and in having his Bill taken up for discussion. So, when this opportunity is there. I appeal to my friends and to the Government and all my friends kindly to take away this cancer from the organic law of the country. It is nothing but cancer. I am requesting the hon. Minister here to cite a single instance to the satisfaction of this House, when this has been properly used, at any point of time.

Apart from this, the trade union movement in this country which is based on democratic rights, cannot be stifled by having provisions like these in our Constitution. This is the time when Government should rise to the occasion. I hope they will issue a whip that this Bill should be passed and supported by their people unanimously, without any opposition. Thank you.

MR. CHAIRMAN: Before I call the other hon. Members, may I just tell the House that the time fixed for this Bill is over? If the House agrees, the time can be extended further.

“
 भय तथा संशय का कार्य मंत्रालय में राज्य नहीं।
 (श्री सारंग साय) : भय और संशय चाहते हैं तो हमें कौटु
 भाषित नहीं है कोई व्यवस्था नहीं है।

MR. CHAIRMAN: How much time do you want?

श्री लारंग साय : अगर माननीय सदस्य दो मंदा चाहते हैं तो समय बड़ा दिया जाय, हमें कोई आपत्ति नहीं है ।

MR. CHAIRMAN: I have only four speakers at the moment. Then the hon. Minister has to intervene in relation to that. So, is it the pleasure of the House to extend the time of the discussion by two hours more?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

MR. CHAIRMAN: Mr. Vayalar Ravi.

SHRI VAYALAR RAVI (Chirayinkil): Mr. Chairman, Sir, I support this Bill after hearing the eloquence of Mr. Somnath Chatterjee as well as our new friends from the Congress (I) side. Mr. Somnath Chatterjee, who is privileged to argue many cases, has put forward his jurisprudence and the legal morality behind the arguments which I do not want to go into detail. Of course, he has made a reference about cancer because this provision gives protection to all the legislations that you have made and are making in the name of the service security as well as discipline. This is a major provision which is always a dagger against the employment security of the entire State as well as Central Governments' services. This is the main point. Here, I can illustrate with examples how it has been used as well as threatening to use against the employees and still they are afraid to anything to protect their rights.

I go one step further and say that these two provisions of the Indian Constitution. Arts. 310 and 311 are to protect, as I usually say, modern slavery of this modern country. Naturally he is doing it. Mr. Patel is a good Minister and a good Home Minister also. I do not know whether he has any occasion to look into the service conditions and the pitiable posi-

tion of the central industrial security force. It is coming under which department, I do not know. I do not know whether they come under reference or the other section, but they have been treated on par with the Defence services. You must be surprised to know that the persons who have been recruited for the last 10 years are still temporary. They have not been made permanent so far; and they have to put in 8 hours service. Please listen to me because this is very important and I will tell you how this provision is used against them. They have been guarding the public sector. Then they have to go for PT inspection and all sort of military training. What is their pay? It is mere Rs. 344. And what instructions you have issued? You have issued instructions that they should not have a mess bill for more than Rs. 60. Our D.A. is Rs. 51/- per day. You are using this force even against the working class. You have made a restriction that they cannot have a mess bill for more than Rs. 60/-. Please check your files. They are living like slaves at the mercy of the officers. How do the officers live? They live with big paraphernalia, say, 3-4 cars in the public sector companies and then these people as their servants in their quarters. I can prove it. I have seen it with my own eyes. I asked them. "Why can you not revolt?" They said, "We will lose the job. I said "How". They said, "Under Art. 310." They can be dismissed immediately. That is why. I say you are making it as a dagger against their interest. This force came into being by an enactment. This provision has been protected by this clause. I do not want to go into detail what is happening in all these posts. But with your permission, I make this observation that 14 per cent of the people, by law, are provided with accommodation for family, but not a single one of them has been given any accommodation.

You take the case of CRP. What is their condition? These come under

[Shri Vayalar Ravi]

Defence forces. I had to put a lot of questions during and before the emergency to say that their conditions should be improved. Mr. Chairman, you will be surprised to know that during the emergency, one Commander put a chain round the neck of the CRP constable and carried him in the streets of Palaghat in Kerala. I went to the Home Minister and asked him, "What is going on. Are they slaves?" In the CRP, slavery is more. This is only an example of the service conditions of personnel of para military service. They are all covered by this kind of provisions against which they cannot revolt or make representation. I appeal to the Minister; he must have a look at it, instead of going through the report of the I.G. sitting in the Secretariat or so called commandant who is living in such an affluent way, using three or four jawans as his servant. You should not use this clause against them. But so far as this clause is there, it will be used against them. You can say that you need that weapon to control them and to maintain discipline; but it is actually enabling them to maintain slavery; that is my objection.

Shrimati Parvathi Krishnan mentioned about the P & T employees. Out of five lakhs, about 2.3 lakhs are extra-departmental employees. I would call them slaves. They are the lowest paid people in the country today. In the new set up introduced by the Janata government, he has to carry Dak, sort out letters, should work as stamp vendor and do many other things. Although he works more than 8 hours, is he getting the minimum salary? He is not getting the minimum salary; although he works in the villages for more than 8 hours. They are called extra departmental people and are treated in the most humiliating manner; they are at the mercy of the postal inspectors in every taluk. In this Parliament, from this side and that side

there is glamour that some benefit should be given to these people. Nothing has been done. Can they revolt? Immediately comes 310 or 311 either directly or through other legislation in which they had been incorporated. I, therefore appeal to the hon. Minister: please examine this problem. There are temporary employees in the state and in the central services, who remain unconfirmed even after five years of service. There are lakhs of such employees. What protection have you given to them? Previous government did the same thing; you are doing the same thing. This has become the system in the country. The officers in the north block and the south block think that you and I come and go but they are permanent people there, why bother about these things. (An Hon. Member: Your party was there). I am also equally to blame. Now those officers know that that party has gone and the Janata party has come but the Janata party also will go; they do not bother. Unfortunately the bureaucrats think that ministers depend upon them. Let us change that attitude. They want to keep people temporary and take away all the rights. Because of these two provisions in the Constitution, whether they are government servants or defence service men or other employees, they are unable to do anything. Take the audit department. There is one case in Kerala; the secretary of a union has been dismissed. He was opposed to my union; I know that. But if the dismissal has been done for political reasons, this provision is a political weapon, it is a weapon in the hands of the administration. That is why Shri Somnath Chatterjee argued that you should see whether this political weapon can be allowed to be used. It has been used once upon a time, again by our party now you are using it against other people.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE:
The victims are the same.

SYRI VAYALAR RAVI: The employer of this weapon has changed. This should be put an end to. A reply will come, I know, from the Minister that to maintain discipline and order in the services this has to be continued.

SHRI SOMNATH CHATERJEE: Why is it not made applicable to Ministers also?

SHRI VAYALAR RAVI: No other legalistic jurisprudence you can make. So, I do not want to take much of your time. I am grateful that you allowed me to speak. Arguments have been put forward—legalistic arguments, and cases have been cited—Supreme Court case as well as Calcutta High Court case. I hope the Minister will go into the details and the provisions and also the experience that we have of different forces—Inter Security Force, CRP, BRP, Railways Lakhs and lakhs of temporary workers remain with the Central Government as well as the State Government. Please have a look at their problem from humanitarian angle and try to see and behave like a civilian Government and civilized Government to protest their interests.

With these words I support the Bill.

श्री उपसैन (देवरिया) चेयरमैन साहब, जो विधेयक माननीय भगत राम जी ने यहाँ पर पेश किया है, मैं तो बहुत दिनों से, सविधान में जो खामियाँ थी उन के खिलाफ लड़ता आ रहा हूँ। अब यह मैं कैसे कहूँ कि लड़ते लड़ते तबाह हो गया हूँ, मैं तो समाजवादी हूँ, मैं कभी निराशावादी नहीं हो सकना। इस के उद्देश्य में ठीक लिखा है कि विक्टोरिया काल के जमाने से, 1935 के एक्ट में यह आ गया और फिर मच्छिका स्थाने मच्छिका लगता चला गया। फिर किसी ने भी इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। श्री वयालार रवी और मेरे साथी दोस्त श्री सोमनाथ चटर्जी ने कानून की बातें कही। मैं तो कानून पढ़ा नहीं हूँ। लेकिन आई पी सी में इतने चालान पिछले चालीस वर्षों में हो चुके हैं कि मुझे भी कानून का काम सेन्स आ गया है, मैं जानता हूँ कि कैसे बरखास्त दी जाती है और कैसे नहीं दी जाती है।

मैं अपनी सरकार का किस्सा बतलाना चाहता हूँ। अपनी बातें भी हमें खुल कर कहनी चाहियें, उत्तर प्रदेश में 12 हजार अपराधी और कृषि विभाग के

अमीन निकास दिए गए। मोहितरिया के इमाने में निकास दिए थे। जब हमारी सरकार आई तो माननीय राजेन्द्र मिह के पास हम गए और कहा कि 12 हजार में 19 वर्ष की मरिस वाले लोग भी हैं, इन को आप कैसे निकाल सकते हैं तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जगह नहीं है। हम ड्राइव्यूमल में दरखास्त देने गए तो कहा गया कि नहीं हो सकता है। आई कार्ट में गये तो कहा गया कि 310 और 311 में सरकार का पूरा अधिकार है वह निकाल सकती है और उस की आई सुनवाई नहीं होगी। गरीबा की युनियन के लोग आज़ भी धनधान कर रहे हैं। हम ने बहुत कॉमिशन की लेकिन दर्द बढ़ता गया, ज्यो ज्यो हमने दबा की। मैं चाहता था कि जब हमारा सविधान बदला जा रहा है तो उस में इस की जगह पर भी कोई अच्छी चीज़ लिख दी जायें, प्रभार राज्य सभा में विरोधी दल के लोग उस को रोकते तो पाप उन के मत्थे चढ़ेगा, हमारे मत्थे नहीं।

एक केंस में और रफ़र करना चाहता हूँ जिस में मैं खुद इवाल्ड था। उत्तर प्रदेश की विधान सभा का एक बड़ा सुन्दर केंस हो गया है, केशवसिंह का केंस, जिस को तमाम दुनिया की ला कार्टर्स में कोट किया जाता है। मदन की अवमानना के लिए केशवसिंह को सात दिन की जेल हो गई। पाच दिन से जेल में रहे। मैं यहाँ आया तो डा० लाहिया जी ने कहा कि सात दिन का सेन्टेन्स सर्व हो जायगा, तुम किसी तरह से रात को उन को छुड़वा लो। एम जस्टिस बेंग के यहाँ गए और दरखास्त दी। उन्होंने प्राविजनल बेल दे दी, कुछ पूछा ही नहीं। उस के बाद विधान सभा में प्रश्न उपस्थित हो गया, हमारे जज साहब पर, हमारे वकील पर और केशव सिंह पर उन्हे मुकदमा चल गया। हम हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट के जज ने स्पीकर साहब पर वारंट काट दिया। मैं ने कहा स्पीकर साहब आप बैठे रहिएगा, आप का वारन्ट नकर हम धायेंगे। इधर जज साहब या वारन्ट विधान सभा में काट दिया, जस्टिस बेंग का जो कि बाद में चीफ जस्टिस हो गए। रात को जस्टिस मूला मेरे पास आये और कहा कि जस्टिस बेंग बहुत एजिटेटेड है। रात को 11 बजे जब मैं पहुँचा तो पूछा कि आप क्या परेशान हैं, आप ता ध्यान रेबिल जस्टिस है हाईकोर्ट बेंच के उन्होंने कहा, यह उन के शब्द हैं

Am I immune from law?

मैंने कहा—मैं कानून से तो छुटकारा नहीं दिना सकता, लेकिन फिलहाल दरगा जो गिरफ्तार करने नहीं धायेंगे, इस को गारंटी मैं देता हूँ। इस केशव सिंह केम पर बहुत हल्ला हुआ। बाद में राठुपति जी ने इस केम को गजेन्द्र गडकर साहब को रफ़र कर दिया। इस को बाद में "केशवसिंह रेफ्रेन्स केम" कहा गया। उन्होंने इस में क्या होल्ड किया? उन्होंने होल्ड किया कि धान-रेबिल कोर्ट को अधिकार है कि बिना सफाई निये प्रीविजनल जमानत दे सकते हैं। बिना चार्ज कीट दिए, बिना जबाब लिए किसी भी धादमी को बन्दी नहीं किया जा सकता है। एम लोग उस में जीत गये और उस समय की जो सरकार थी, वह हार गई। आज दुनिया में यह केंस साइट होता है।

[श्री उष सेन]

310 के आर्बिटर में लिखा हुआ है कि सरकार उस में बाहे तो कुछ कर सकती है, लेकिन उस तरफ कौन देखता है। मालिकान क्या करते हैं, सिर्फ़ अपने फायदे की चीज को देखते हैं। प्रान्तरियल हार्ड कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किसी मामले में कोई फैसला करते हैं मगर जब एग्रेसन का मबाल धाता है तो वहा कोई सुनवाई नहीं होती है। राज्य सरकारों ने अपने यहां कर्मचारियों के लिये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाये है, यह सब घोषणाखड़ी है फाइ है, ये कर्मचारियों का सत्यानाश करती है। ट्रिब्यूनल के कायदे क्या है? ये फैसला कर दे कि अमूक आदमी का बहाल कर दिया जाय, लेकिन माथ ही उस के अन्दर यह बाव भी लिखी है कि यह ज़रूरी नहीं है कि सरकार उस को जाने। तब इन के फैसले के क्या मायने हैं? रोड-वेज ड्राइवर्स या कण्ट्रैक्ट में के बारे में यह फैसला होता है कि ये बिल्कुल दोष मुक्त हैं, इन के ऊपर कोई दोष नहीं है, ता भी सरकार उस को नहीं मानती है, लेकिन यदि ट्रिब्यूनल लिखता है कि इन को बिल्कुल डिमिशन कर दिया जाय, ता सरकार फौरन उस को मान लेती है। इसीप्रकार कर्मचारियों के जितने सच हैं, जिनकी यूनियन है, हम जा उन में काम करते हैं, हम सब को यह माय है कि भारतीय मालिकान में से सपोर्टिबल 310 और 311 का बिल्कुल उडा दिया जाय और पाटिल साहब में आप में दम्नदम्ना यह माग करना हू-हूम गरीबों पर क्या कीजिये, अगर मैं हूक मायन की बाव कहूया तो आप लड जायेंगे। हम माग मारा लगाते थे-अपनी माग नड कर लेगे। लेकिन अब हमारी ही पार्टी सत्ता में बैठी है। हम लिये हम मावने हैं कि अब नारे से काम नहीं चलेगा, अब कुछ मुद्दत से काम किया जाय। मैंने बाइबिल भी जेल में पडा और कुदान भी जेल में पडा। मभापनि महोदय, मेरा कोई खुदा या भगवान नहीं है। मैंने इन सब का इतिहास कर दिया है। मैं जब विद्यार्थी था, तब से ही सब को इतिहास कर दिया था। उन्होंने बहुत थ लील की, लेकिन मैंने मजूर नहीं किया।

समापति महोदय : आपने उन को कारण बतलाया ? उन का कोई फा-कात्र नोटिस दिया था या नहीं ?

श्री उषसेन : वे 6 महीने तक प्राथी तनबवाह पाने रहे, मैंने उन का पूरा मौका दिया।

समापति महोदय : आप की चार्जशीट का जबाब दिया ?

श्री उष सेन : जी हा, उन्हा ने दिया, लेकिन उस में कुछ नहीं था। मैंने रोडवेज वाले लिखते हैं-मुम्हारी अग्रील में कोई फोर्स नहीं है, उसी तरह से हमने लिख दिया कि मुम्हारी अग्रील में कोई फोर्स नहीं है।

लेकिन, मभापनि महोदय, मैं उन की बातों को मानता हू। मैंने कुदान पढ़ा, उस के मैलिगन्ट फीचमें पर मैंने भाषण भी दिया। बाइबिल में लिखा है-अगर तुम किसी के लिये गड़डा खादने जाओ, तो कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे लिये ममूड या खार्ड खुद जाय। इस का मनलब क्या है? स्टेट जो शाषण की मसीनरी का प्रापरेटर है, धारा 310 और 311 के अन्तिस मरे के अन्तर्गन जा शाषण किया जाता है, कले-आम किया जाता है, उस की सुनवाई कही नहीं है।

भगतराम जो, आप का विमान इतर कैसे गया ? हम तो आप को बहुत सीधा-सादा समझते थे, लेकिन आप तो,

सतलैया के दोहरे ज्यो नाविक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गम्भीर।

आप ने यह बात करके विन्धला दी है। हम बाकी में आप को बहुत सीधा-सादा, हार्मलैम - कीबर समझते थे, लेकिन आप ने इस बिल को ला कर जा चोट की है, सही मायनों में हमारे पटेल साहब को, जो मेरे बहुत बड़े दास्त है, मैं उन का बहुत धारर करता हू, उन को इस बाव का मान लेना चाहिये। आप सविधान में दूसरे सशोधन लाने वाले हैं, माथ में इन दोनों धाराओं को निकालने वाला सशोधन भी आ जाय तो कोई हर्ज नहीं है। सोइतराफा ने तो हजारों सशोधन कर डाले, यहा तक सशोधन कर डाला कि उन के ऊपर, उन के लडके के ऊपर, उन के पाते के ऊपर कोई मुकदमा नहीं चला सकता और इन मामने में बैठने वालों ने और पालियामेंट की इन्ही दीवारों के बीच वह सब मजूर हो गया।

आज जब मैं बोल रहा हू तो आज डा० लोहिया का जन्म दिवस है। यह वही असेम्बली है जहा भगन सिंह ने बम मारा था। जब उन्होंने बम मारा था तो उन को डर के बारे कोई पकड नहीं रहा था। वे डर के मारे पकडे नहीं जा रहे थे। जब अदालत के सामने उन का कम सुना जा रहा था तो उन्होंने कहा था कि मेरा बम मारने वाला बम नहीं था, मैं तो बाहरी दुनिया को सुनाना चाहता था। आज के दिन उन भगत सिंह की भी मुझे याद आ गयी है। ये बान महान नेता थे जो मरे नहीं थे मारे गये थे, डा० लोहिया भी मरे नहीं थे और भगन सिंह भी मरे नहीं थे। उन्हें फासी पर चढ़ाया गया था और डा० लाहिया को गलत नस्तर लगा दिया गया था। उस के कारण उन की मौत हुई थी। मैं उस समय क्रान्तिकारी पार्टी में था। अगर उस समय के कायदे के नेनागण ने थाडा सा भी भगत सिंह का साथ दिया होता तो उन को फासी पर न चढ़ाया गया होता। अगर डा० लाहिया का गलत नस्तर न लगाया गया होता तो वे भी नहीं मरते। इसलिए मैं कहना चाहता हू कि तलवार का कोई दोष नहीं है। अगर तलवार आप के हाथ में है तो आप मेरी गरदन उबा सकते हैं और मेरे हाथ में हो तो मैं आप की गर्दन उडा सकता हू। बोध तो उस की मुट्ठी का है जिसे कि पकडा जाता है। अग्रे जो ने क्या किया, विकटोरिया से ले कर उस के बेटे-पोते तक करते आये। अभी भी ब्यालार रॉय साहब बोल रहे थे। इन्होंने भी यही किया जिन को कि अग्रेजों के बाव शासन करते को भिसा। अब हम बी साल से हैं। कहा जाता है कि "पर अचना जल गया अपने चिराग से।" हम बड़े खुश हैं। आप मुलाहिजा फरमाइये कि यह काम तो होने का नहीं है।

मैं कहना चाहता हू कि राज्यपाल के लिए लिख देते हैं कि उन के प्लेजर से, वे भायद प्लेजर की स्पेसिग नहीं जानते होंगे, लेकिन प्लेजर का इस्तेमाल करते हैं। उन की कृपा से, महान कृपा से लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाता है। मैंने तो कभी नौकरी की नहीं। बम्बई में बड़ी गरीबी थी। हम बिना बिभी के बड़ा मास्टर हो गये। पता चला कि हमारे पास डिग्री-डिप्लोमा नहीं

है तो निकाल दिये गये। अगर कुछ करते तो डी० आई० आर० में पकड़ जाते। मैं आप को कहना चाहता हूँ कि हम तो उस पार्टी से आते हैं जिस ने यह तय किया था कि कलेक्टर और राज्यपालों के पद बिल्कुल समाप्त कर दिये जाने चाहियें। मैं ने कलकत्ता में आप का राज-भवन देखा है। वहाँ मैं अपने मित्र, जिगर के टुकड़े, अपने मुख्य मंत्री से मिलने गया था। मैं तो उस भवन को देखता ही रह गया। ऐसा भवन जिस को देख कर बंगाल की मशालें जल जाएँ। उस बंगाल की जिन के लोगों ने बम और पिस्तौलों से काम लिया, जहाँ के छोटे छोटे बच्चे अड़ गये। उन में कितनी हिम्मत थी? आप जानते हैं कि ये बड़े बड़े भवन क्यों बनाये जाते थे? इसलिये बनाये जाते थे कि गरीब जनता उन को देख कर डर जाये और यह समझे कि उन में शेर रहते होंगे, बेशक वहाँ गीदड़ ही रहते हों। गांधी जी और डा० सोहिया कहा करते थे कि इन भवनों को संग्रहालयों, स्कूलों और अस्पतालों में बदल डालो और मामूली मकानों में रहो। वे ऐसे साधारण मकानों में रहने को कहते थे जैसे कि मैंने केरल में देखे। केरल में गांव नहीं है। सादे से, ऊपर से पत्तों से बिछाये हुए घर हैं। मुझे वे घर बहुत पसन्द आये। हमारे उत्तर प्रदेश में तो बड़े बड़े घर हैं, छतें आसमान से बात कर रही हैं, चाहे सोने के लिये जमीन नहीं है। तो मैं कह रहा था कि इन राज्यपालों का पद ही डाउटफुल है। हमारे बेटों बाबू बैरिस्टर हैं। अगर कोई मुकदमा दाखिल कर दें कि राज्यपालों का कोई औचित्य नहीं है और संविधान को पढ़ कर मुना दें तो मुश्किल हों जाय। कहा जाता है कि "दि किंग आफ इंग्लैंड कौन हूना रोग"। केन आई डू ए राइट थिंग? इसलिये मैं कहता हूँ कि राज्यपाल तो भाग्य विधाता हैं। आप ट्रिब्यूनल को पहले निकालिये। ये फर्जी ट्रिब्यूनल बने हैं। इन का ट्रायल होता है। ऐसा ट्रायल होता है जैसा कि पाकिस्तान में मूटों का ट्रायल हुआ है, बंगला देश में ट्रायल हुआ है। ये सब ट्रायल दिखाने के लिये होते हैं। अपने वकील दोनों हरफ रख दिये जाते हैं और फंसला हो जाता है। मुकदमा चल जाता है। ये दोनों धारायें 310 और 311 तो बिल्कुल निकाल देनी चाहियें। मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि इस में कोई विट्प की बात नहीं है। हमें सिद्धान्त की बात है। समाजवादी होने के नाते और ट्रेड यूनियन मूवमेंट में काम करने के नाते मैं बिल्कुल मुत्तमईन हूँ कि इन आर्थों को निकाल देना चाहिये इन और धाराओं के छूते जनता के नागरिक अधिकार कतई रह नहीं सकते हैं। हमारी आवाज तो बेअसर हो रही है और जिस की आवाज बेअसर होनी चाहिये वही अस्तरदार हो रही है। मैं यहाँ आज भी हैस्टिंग रोड, क्लाइव रोड, बनरो रोड आदि सड़कों के नाम लिखे देखता हूँ तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। क्या आप ने इंग्लैंड में विवेकानन्द रोड, जवाहरलाल नेहरू रोड, आदि रोड्स के नाम कहीं देखे हैं। यहाँ पर क्यों सड़कों के नाम इस तरह से रखे गए हैं? यह गुलामी के दिमागों की उपज है। मैं जनता पार्टी की सरकार से विनती करता हूँ कि वह इस विधेयक को माल लें। शान्ति भूषण जी चले गए हैं। उन को यहाँ होना चाहिये था। अगली बार मैं चाहता हूँ कि वह आएँ और हमें कानूनी बातों को बतायें और हमें बढ़ाएँ कि 310 और 311 प्रिप्लवल् आफ दी कांस्टिट्यूशन

जो संविधान का हैं, उस के तहत यह आता है या नहीं और अगर नहीं आता है तो यह रिडंडेंट है, इस को निकाल देना चाहिये क्योंकि सिद्धान्त दूसरे हैं, अलफाज दूसरे हैं।

इन शब्दों के साथ मैं श्री भगतजराम के संशोधन का समर्थन करता हूँ और आशा करता हूँ कि यह सदन भी इस का समर्थन करेगा।

श्री श्रीम प्रकाश त्यागी (बहराइच) : मैं इस विधेयक का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। इसके उद्देश्यों और लक्ष्यों में इन्हीं ने जो जिज्ञा है मेरा उसी से मतभेद है। यह कहते हैं कि 1897 में विक्टोरिया ने अपनी सुरक्षा के लिए कुछ कानून बनाए और दुर्भाग्यवश उन सबको हमारे संविधान में ला कर रख दिया गया है। ऐसी बात नहीं है। हमारे संविधान निर्माताओं ने अंग्रेजों के कई कानूनों को ज्यों का त्यों ले लिया है और अमरीका के बने हुए कानूनों को भी ले लिया है। मैं नहीं समझता हूँ कि इन में कोई बुरी बात है। भावना की बात को आप को देखना चाहिये। जनता पार्टी की गवर्नमेंट किस भावना से इस को बनाए रखना चाहती है और विक्टोरिया ने किस भावना से बनाया था, दोनों अलग अलग हैं। संविधान निर्माताओं ने किस भावना से इन को स्थान दिया और विक्टोरिया की क्या भावना थी इन दोनों में मतभेद है। अभी श्री उपसेन ने कहा कि तलवार एक ही होती है। मैं कहना चाहता हूँ कि तलवार का प्रयोग तलवारकर्ता पर निर्भर करता है। डाकू के हाथ में आ जाए...

श्री० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : परिणाम एक ही होता है।

श्री श्रीम प्रकाश त्यागी : चीज एक है लेकिन उसका प्रयोग करने वाले अलग अलग हैं। किसी आदमी ने अगर उस का गलत प्रयोग किया है तो इस का मतलब यह नहीं है कि उस चीज के अस्तित्व को ही समाप्त कर दिया जाए। अगर डाकू के हाथ में आ गई और उसका गलत प्रयोग हुआ तो इस का मतलब यह नहीं कि सिपाही के हाथ में तलवार न दी जाए.....

MR. CHAIRMAN: The hon. Member may continue his speech the next day.

18.00 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, the 26th March, 1979 (Chitra 5, 1901 (Sakha)).